

## प्राथमिक क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन का विश्लेषण: 2014-15 से 2018-19

राष्ट्रपति ने संसद में अपने अभिभाषण के दौरान पिछले चार वर्षों की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। इस नोट में उन प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है। नोट में निम्नलिखित मदों में सरकार की पहल की मौजूदा स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। नोट 30 जनवरी, 2018 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। डेटा के स्रोत एंडनोट्स में दिए गए हैं।

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
<b>अर्थव्यवस्था और वित्त</b>	
<p><b>राष्ट्रपति के अभिभाषण 2014-2018:</b> विश्व स्तर पर आर्थिक उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च स्तरीय वृद्धि बरकरार रही। जीडीपी में भी निरंतर वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटे और मौजूदा चालू खाता घाटे में औसतन गिरावट दर्ज की गई।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>वृद्धि दर:</b> 2018-19 के दौरान जीडीपी में 7.2% की दर से वृद्धि का अनुमान है। 2017-18 में 6.7% से अधिक वृद्धि हुई थी।<sup>1</sup> पिछले पांच वर्षों के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर प्रति वर्ष 7% और 8% के बीच रही। 2017-18 में इसमें गिरावट हुई और यह 6.7% हो गई। यह विमुद्रीकरण का वर्ष था।<sup>2,3,4,5</sup></li> <li>▪ <b>मुद्रास्फीति:</b> वित्त मंत्रालय ने 2016-2021 की अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति के लिए 4% का लक्ष्य रखा है।<sup>6</sup> मुद्रास्फीति के लिए ऊपरी सीमा 6% और निचली सीमा 2% रखी गई है।<sup>7</sup> 2014 और 2018 के बीच सीपीआई इस सीमा के भीतर रही।</li> <li>▪ 2018-19 की पहली तीन तिमाही में <b>सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति</b> 2% और 4% के बीच रही।<sup>8</sup> 2016-17 में सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति 3% और 5% के बीच रही।<sup>9</sup></li> <li>▪ <b>राजकोषीय घाटा:</b> 2018-19 में इसके जीडीपी के 3.3% (6,24,276 करोड़ रुपए) पर रहने का अनुमान है, जबकि एफआरबीएम का मैनडेट 3% का है।<sup>10</sup></li> </ul>

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए।

जून 2016 में विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नीति को उदार बनाया गया।

तालिका 1: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा, वास्तविक बनाम लक्ष्य<sup>11</sup>

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वास्तविक	4.1%	3.9%	3.5%	3.5%
लक्ष्य	4.1%	3.9%	3.5%	3.2%

- **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई):** 2016-17 में 60.2 अरब यूएसडी की तुलना में 2017-18 में एफडीआई प्रवाह 62 अरब यूएसडी पर पहुंच गया।<sup>12</sup> 2014-15 से 2017-18 के दौरान एफडीआई में 13% की वार्षिक कंपाउंड दर से बढ़ोतरी हुई।
- 2017-18 के दौरान सरकार ने एफडीआई नीति में कुछ परिवर्तन किए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं (i) सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में ऑटोमैटिक रूट से शत प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी, और (ii) जनवरी 2018 में विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में 49% तक के निवेश को मंजूरी।<sup>13</sup>
- जनवरी 2019 में **विदेशी मुद्रा भंडार** 397 अरब यूएसडी हो गया, जबकि मई 2014 में यह 313 अरब यूएसडी था।<sup>14,15</sup>
- **चालू खाता घाटा (सीएडी):** 2018-19 की पहली तिमाही में सीएडी बढ़कर जीडीपी के 2.4% पहुंच गया।<sup>16,17</sup> 2018-19 की दूसरी तिमाही में 50 अरब यूएसडी के **उच्च व्यापार घाटे** के कारण सीएडी में वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में 32.5 अरब यूएसडी का व्यापार घाटा हुआ था।
- **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी):** 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया गया।<sup>18</sup>

एक देश-एक कर और एक देश-एक बाजार के जरिए सहयोगपरक संघवाद की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की। जीएसटी स्वतंत्रता के बाद से देश का सबसे बड़ा कर सुधार रहा।

<p>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त गवर्नेंस संबंधी प्रमुख सुधार किए गए।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2015 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए <b>इंद्रधनुष योजना</b> की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार वित्तीय वर्षों के लिए 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी दिए जाने का लक्ष्य रखा गया।<sup>19</sup> 2017 में सरकार ने इन बैंकों को 2,11,000 करोड़ रुपए की राशि देकर पुनर्पूँजीकृत करने के फैसले की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्पूँजीकरण की राशि 88,139 करोड़ रुपए कर दी गई।<sup>20</sup></li> <li>▪ <b>बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीएज़):</b> अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सकल एनपीएज़ मार्च 2014 में 3.8% से बढ़कर मार्च 2017 में 9.3% हो गए। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह आंकड़ा 4.4% से 11.7% हो गया।<sup>21</sup></li> <li>▪ <b>इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (आईबीसी):</b> मई 2016 में आईबीसी को पारित किया गया ताकि कंपनियों और व्यक्तियों की इनसॉल्वेंसी के रेज़ोल्यूशन के लिए समयबद्ध प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। यह संहिता इनसॉल्वेंसी को रिज़ॉल्व करने के लिए 180 दिन की समय सीमा तय करती है जिसे 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान व्यवसाय जारी रखा जा सकता है।<sup>22</sup> दिसंबर 2018 तक इस संहिता के अंतर्गत 1,484 मामले पंजीकृत किए गए हैं और 381 मामलों को रिज़ॉल्व किया गया है।<sup>23</sup></li> </ul>
<p>भ्रष्टाचार, काला धन और नकली करंसी से संबंधित उपाय किए जाएंगे, हालांकि सार्वजनिक हित में सिविल सर्वेयर्स द्वारा लिए गए फैसलों को संरक्षण देने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 3.5 लाख संदिग्ध कंपनियों के पंजीकरण को रद्द किया गया है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>विमुद्रीकरण:</b> 8 नवंबर, 2016 को सरकार ने 500 रुपए और 1,000 रुपए के करंसी नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की जिनका कुल मूल्य 15.42 लाख करोड़ रुपए था। सर्कुलेशन वाले कुल नोटों में ऐसे 86% नोट थे।<sup>24</sup></li> <li>▪ आरबीआई की 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 जून, 2018 तक 15.31 लाख करोड़ रुपए के विमुद्रीत नोट (99.3%) आरबीआई में वापस आ आए। रिपोर्ट कहती है कि जून 2017 तक अनुमानित 11,000 करोड़ रुपए के विमुद्रीत नोट वापस नहीं आए।<sup>25</sup></li> <li>▪ अक्टूबर 2016 और नवंबर 2018 के दौरान डिजिटल भुगतान 180% (कार्ड्स) और 256% (तत्काल भुगतान सेवा) बढ़ गया।<sup>26</sup></li> <li>▪ नवंबर 2016 से अक्टूबर 2017 के दौरान 24,800 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला।<sup>27</sup></li> </ul>

<p>कराधान कानून (दूसरा संशोधन) एक्ट, 2016 में प्रस्तावित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के परिणामस्वरूप काले धन से संघर्ष के लिए व्यापक नीति बनाई जाएगी।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस योजना के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं।<sup>28,29</sup></li> <li>▪ 2015 में संसद ने <b>अघोषित विदेशी आय और एसेट्स (कराधान) बिल</b>, 2015 पारित किया। यह बिल विदेशी आय वाले भारतीय निवासियों पर कर लगाता है। यह विदेशी आय छिपाने पर दंडित करता है और उस पर कर देने से बचने वालों को अपराधी घोषित करता है।<sup>30</sup></li> <li>▪ <b>भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल, 2018</b> को जुलाई, 2018 में पारित किया गया। बिल उन आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का प्रयास करता है जिन्होंने आपराधिक अभियोग से बचने के लिए देश छोड़ दिया है।<sup>31</sup></li> <li>▪ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) बिल, 2013 ने भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, 1988 में संशोधन किया। सरकार ने 2015 में बिल में कुछ संशोधनों को सर्कुलेट किया। 1988 के एक्ट के अंतर्गत सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेना एक अपराध था। बिल रिश्वत देने को भी अपराध बनाता है।<sup>32</sup></li> </ul>
<p>वित्तीय समावेश और गरीबी उन्मूलन सरकार का अति महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। सरकार गरीबों, किसानों और वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक असुरक्षा को दूर करने का काम कर रही है।</p> <p>प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम को लागू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि विकास कार्यक्रम लीकेज और दूसरी बाधाओं के बिना लाभार्थियों तक पहुंचें। कुल मिलाकर 35 योजनाओं को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया गया है। जन धन-आधार-मोबाइल की तिकड़ी के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने लीकेज को रोका और 36,000 करोड़ रुपए की बचत में मदद की।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>जन धन-आधार-मोबाइल (जैम तिकड़ी) के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):</b> 2013 में अपनी शुरुआत से 7 जनवरी, 2019 तक इस कार्यक्रम के जरिए 437 योजनाओं के अंतर्गत और 55 मंत्रालयों द्वारा 6.05 लाख करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया गया है।<sup>33</sup></li> <li>▪ सरकार के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके जरिए कुल 90,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस प्रक्रिया में 2.7 करोड़ नकली राशन कार्ड्स और 3 करोड़ फर्जी एलपीजी कनेक्शंस को चिन्हित किया गया।<sup>34,39</sup></li> </ul>

**तालिका 2: डीबीटी में बढ़ोतरी<sup>33</sup>**

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
डीबीटी के जरिए संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	38,926	61,942	74,689	1,90,871	2,32,105
डीबीटी लाभार्थियों की संख्या (करोड़ रुपए में)	22.8	31.2	35.7	124	125.2

नोट: 2018-19 के डेटा 27 जनवरी, 2019 तक अपडेट किए गए हैं।

सभी को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया। योजना शत प्रतिशत कवरेज प्रस्तावित करती है। अपनी शुरुआत के छह महीने के भीतर रिकॉर्ड 13.2 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए और 11.5 करोड़ रुपये डेबिट कार्ड जारी किए गए।

- **जन धन योजना:** 23 जनवरी, 2019 तक 34.03 करोड़ जन धन खाते खोले गए। इनमें से 20.14 करोड़ (59%) खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। इनमें 88,566 करोड़ रुपए जमा किए गए और 27.17 करोड़ रुपये डेबिट कार्ड जारी किए गए।<sup>35</sup>

**तालिका 3: जन धन योजना के अंतर्गत उपलब्धियां (कुल मिलाकर)<sup>36</sup>**

	जनवरी-16	जनवरी-17	जनवरी-18	जनवरी-19
खोले गए	20,46,78,690	27,30,81,870	31,03,74,800	34,03,00,587
खाते				

नोट: 2018-19 के डेटा 23 जनवरी, 2019 तक अपडेट किए गए हैं।

आधार के कवरेज को सार्वभौमिक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

- **आधार:** 2018 के लिए अनुमानित जनसंख्या के आधार पर 31 दिसंबर, 2018 तक 90.1% लोगों के पास आधार है।<sup>37</sup> 1.2 अरब कार्ड जारी किए गए।<sup>37</sup>
- **मोबाइल:** 2017 में 121 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स थे, जबकि 2016 में यह संख्या 103 करोड़ थी। 2016 में 30 करोड़ की तुलना में 2017 में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़कर 40 करोड़ हो गई। 2016 में जहां इंटरनेट यूजर्स 40 करोड़ थे, वहीं 2017 में यह बढ़कर 50 करोड़ हो गए।<sup>38</sup> 2020 तक इस संख्या के बढ़कर 73 करोड़ होने का अनुमान है।<sup>39</sup>

एलपीजी पर सबसिडी के लिए विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना पहल को देश व्यापी बनाया गया।

- **पहल योजना:** इसकी शुरुआत जून 2013 में की गई और तब से 291 जिले इसके दायरे में आ गए हैं। इसके लिए बैंक खाते में सीधे एलपीजी सबसिडी लेने के लिए उपभोक्ताओं

	<p>के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है।<sup>40</sup> 31 दिसंबर, 2018 तक इस योजना को 715 जिलों में लागू किया गया और इससे 23.2 करोड़ लोग लाभान्वित हुए।<sup>41,42,43</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सरकार के अनुसार 2014 तक पहल के कारण सबसिडी में 29,446 करोड़ रुपए की बचत हुई।<sup>44</sup></li> </ul>
<p>सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए सरकार ने दो बीमा योजनाएं और एक पेंशन योजना शुरू की: (i) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, (ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और (iii) अटल पेंशन योजना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2018 में अटल पेंशन योजना का सबस्क्राइबर बेस 1.24 करोड़ से अधिक हो गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना में 27 लाख नए सबस्क्राइबर्स जुड़ गए (2 नवंबर, 2018 तक)। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक का योगदान इसमें सबसे अधिक है।<sup>45</sup></li> <li>31 अक्टूबर, 2018 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अपना नाम दर्ज कराने वालों की संख्या 14.27 करोड़ हो गई है। 8 सितंबर, 2018 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अपना नाम दर्ज कराने वाले लोगों की संख्या 5.47 करोड़ हो गई है, और 2,208 करोड़ रुपए की राशि के दावों का निपटान किया गया है।<sup>45</sup></li> </ul>
<p>गरीबों और बैंक खातों के बिना लोगों के लिए बैंकिंग प्रणाली को आसान बनाने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक डाक घरों में पोस्टल बैंकों की स्थापना की जाएगी।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अप्रैल, 2018 तक अधिकतम 650 जिलों के पोस्टल बैंकों में भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) स्थापित करने का प्रस्ताव था।<sup>46</sup> 30 जनवरी, 2018 को आईपीपीबी ने दो पायलट शाखाओं की शुरुआत की और 1 सितंबर, 2018 तक देश में सभी 650 जिलों में शाखाएं खोल दी गईं।<sup>47</sup></li> </ul>
<b>कृषि</b>	
<p><b>राष्ट्रपति के अभिभाषण 2014-2018:</b></p> <p>कृषि अधिकतर लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत है। कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना ने जोखिम कवरेज के दायरे को बढ़ाया, किसानों के लिए बीमाकृत राशि को दोगुना किया और प्रीमियम की दरों को कम किया। इसके अतिरिक्त 2016 में ई-नाम प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जोकि</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): प्राकृतिक आपदा, कीटनाशकों या बीमारियों के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से पीएमएफबीवाई को शुरू किया गया। इस योजना में 2016-17 के दौरान 5.7 करोड़ किसानों ने अपना नाम दर्ज कराया, जोकि 2017-18 में 5.2 करोड़ हो गया।<sup>48</sup></li> </ul>

किसानों को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और भारत को एक खाद्य जोन, एक देश, एक बाजार बनाता है।

- 2016-17 के दौरान पीएमएफबीवाई के अंतर्गत 1.4 करोड़ किसानों को कुल 15,350 करोड़ रुपए की राशि के दावों का भुगतान किया गया है। ये दावे 22,550 करोड़ रुपए के प्रीमियम पर चुकाए गए हैं जिनमें किसानों का योगदान 19% था।<sup>49,50</sup>
- 585 बाजारों को एकीकृत करते हुए मार्च 2018 तक ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने के उद्देश्य से अप्रैल 2016 में ई-नाम योजना की शुरुआत की गई। मार्च 2018 तक 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 585 बाजारों को ई-नाम पोर्टल से एकीकृत किया गया। जुलाई 2018 तक 1.1 करोड़ किसानों ने इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लिया है।<sup>51</sup>
- 2014-15 में 500 करोड़ रुपए की राशि से मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई ताकि प्याज, आलू और दालों जैसे महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी उत्पादों की मूल्य स्थिरता को रेगुलेट किया जा सके।<sup>52</sup> सरकार ने कहा कि पीएसएफ के अंतर्गत आबंटित राशि को 20 लाख टन दालों का बफर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 2017-18 और 2018-19 के दौरान योजना के लिए क्रमशः 3500 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया।<sup>53</sup>
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी):** (i) गेहूं के लिए एमएसपी 6.1% और (ii) धान के लिए एमएसपी 6.5% की औसत दर से बढ़ाई गई।<sup>54,55</sup>
- 28 फरवरी, 2018 को कैबिनेट ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए सरकारी गारंटी को 9,500 करोड़ रुपए से दोगुना बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए करना मंजूर किया।<sup>56</sup>

सरकार ने प्रत्येक गांव की सिंचाई संबंधी जरूरतों को सतत तरीके से पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रति बूंद अधिक फसल और हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत की गई।

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई):** सिंचाई कवरेज को बढ़ाने और पानी की उपयोग क्षमता में सुधार करने के लिए 2015 में पीएमकेएसवाई को शुरू किया गया। इस योजना के विभिन्न घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), (ii) पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी, (iii) सतह

लघु सिंचाई, (iv) जल स्रोतों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरोद्धार, (v) पीएमकेएसवाई- प्रति बूंद अधिक फसलस और (vi) पीएमकेएसवाई- वॉटरशेड विकास। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शेयरिंग पैटर्न अलग-अलग घटकों में अलग-अलग होते हैं।<sup>57</sup>

तालिका 4: 2015-16 से पीएमकेएसवाई को आबंटित राशि (करोड़ रुपए में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
संवितरित राशि	7,781	5,134	7,392	9,429

Source: Union Budget Documents

मृदा स्वास्थ्य कार्ड्स वितरित किए जाएंगे और इनसे इनपुट लागत कम होगी। इससे उर्वरकों का उचित उपयोग किया जाएगा और मिट्टी की सेहत में सुधार होगा।

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** के अंतर्गत किसानों को हर दो वर्ष बाद उनकी फसलों के लिए उपयोगी पोषक तत्वों और उर्वरकों के संबंध में सुझाव दिए जाते हैं।
- योजना के पहले चक्र (2015-16 और 2016-17) के दौरान मिट्टी के 2.5 करोड़ सैंपल जमा किए गए और 10.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड्स वितरित करने का लक्ष्य पूरा किया गया।<sup>58</sup>
- दूसरे चरण (2017-18 और 2018-19) के दौरान, 1 जनवरी, 2019 तक 2.5 करोड़ सैंपल जमा किए गए हैं और 12.04 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 7.2 करोड़ कार्ड्स किसानों को बांटे जा चुके हैं।<sup>58,59,60,61</sup>
- 2014-15 से 2017-18 के बीच योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को 406.7 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।<sup>62</sup>

### रोजगार और उद्यमिता

#### राष्ट्रपति के अभिभाषण 2014-2018:

सरकार श्रम सुधारों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। न्यूनतम वेतन 40% से अधिक बढ़ाया गया है।

- 2017 में केंद्र सरकार ने गैजेट अधिसूचना के जरिए कृषि, गैर कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन को 40% से अधिक बढ़ा दिया। गैर कृषि क्षेत्र के अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन (प्रति दिन) को 250 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए, अर्धकुशल मजदूरों के लिए 437 रुपए और कुशल मजदूरों के लिए 523 रुपए कर दिया गया।<sup>63,64,65</sup>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम कानूनों में सुधार और उन्हें सरल बनाने के लिए कदम उठाए। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक कानूनों को सम्मिलित करने वाली तीन संहिताओं के मसौदे जारी किए गए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) <b>औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता</b> का मसौदा, जिसमें ट्रेड यूनियन के पंजीकरण, रोजगार की स्थितियों और विवादों के निपटान से संबंधित कानूनों को सम्मिलित किया गया है, (ii) <b>सामाजिक सुरक्षा पर संहिता</b> का मसौदा, जिनमें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 17 कानून सम्मिलित हैं, और (iii) <b>व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थितियों पर संहिता</b> का मसौदा, जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थितियों से संबंधित 13 श्रम कानून सम्मिलित हैं।<sup>63</sup></li> <li>▪ 2017 में वेतन संहिता बिल लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल वेतन और बोनस भुगतान को रेगुलेट करता है और चार एक्ट्स को सम्मिलित करते हुए उन्हें रिप्लेस करता है।<sup>66</sup></li> <li>▪ 1 अप्रैल 2017 को <b>मातृत्व लाभ (संशोधन) एक्ट, 2017</b> लागू हुआ। यह एकट वैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार इससे 18 लाख महिला कर्मचारी लाभान्वित हुई हैं।<sup>67</sup></li> </ul>
<p><b>राष्ट्रपति के अभिभाषण 2014-2018:</b> एपेरल क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। इससे 1.1 करोड़ नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। कृषि के बाद देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाले टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>संशोधित तकनीकी उन्नयन फंड योजना (ए-टीयूएफएस)</b> मौजूदा संशोधित, पुनर्गठित टीयूएफएस को रिप्लेस करती है और टेक्सटाइल यूनिट्स को 10% अतिरिक्त पूंजीगत निवेश सबसिडी प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इस योजना के अंतर्गत ये यूनिट्स पहले से 15% सबसिडी का लाभ उठा रही हैं।<sup>68</sup></li> <li>▪ केंद्र सरकार ने जून, 2016 में <b>टेक्सटाइल निर्यात में रोजगार सृजन और संवर्धन के लिए विशेष पैकेज</b> को मंजूरी दी। इसमें अन्य इन्सैटिव्स के साथ कार्य के अतिरिक्त (ओवरटाइम) घंटों में सुधार और कर्मचारी भविष्य निधि योजना शामिल हैं।<sup>69</sup> इन सुधारों से तीन वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में 67.1 लाख की वृद्धि की उम्मीद है।</li> </ul>

सरकार ने उच्च तकनीकी शिक्षा को अधिक सुगम बनाया।

- सरकार ने 2017-18 से 2019-20 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तौर पर सिल्क उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 2161.68 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया। योजना का उद्देश्य अनुसंधान और विकास के जरिए 2022 तक सिल्क उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।<sup>70</sup>
- सरकार ने 2015 में **प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना** की शुरुआत की। इसका लक्ष्य युवाओं को उद्योग प्रासंगिक दक्षता प्रशिक्षण हासिल करने में मदद देना है। यह योजना निम्नलिखित के जरिए सहयोग प्रदान करती है (i) अल्पावधि का प्रशिक्षण (एसटीटी), (ii) प्रायर लर्निंग को मान्यता (आरपीएल), और (iii) चार वर्षों (2016-2022) के लिए विशेष प्रॉजेक्ट्स (एसपी)। 30 नवंबर, 2018 तक देश में विभिन्न क्षेत्रों में एसटीटी (24.13 लाख), आरपीएल (9.08 लाख) और विशेष प्रॉजेक्ट्स (0.72 लाख) के अंतर्गत लगभग 33.93 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।<sup>71</sup>

सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यम (एमएसएमई) बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हैं। सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और एमएसएमई की स्थापना को आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

- प्रधानमंत्री द्वारा **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** को 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे। पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ने तीन प्रॉडक्ट्स तैयार किए हैं, 'शिशु' (50,000 रुपए से कम के ऋण), 'किशोर' (50,000 से 5 लाख रुपए तक के ऋण) और 'तरुण' (5 लाख से 10 लाख के बीच के ऋण)।<sup>72</sup>

तालिका 5: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उपलब्धियां<sup>72</sup>

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ऋणों की संख्या	3,48,80,924	3,97,01,047	4,81,30,593	3,28,65,537
मंजूर राशि (करोड़ रुपए में)	1,37,449	1,80,529	2,53,677	1,74,853
संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	1,32,955	1,75,312	2,46,437	1,68,014

नोट: 2018-19 के डेटा 18 जनवरी, 2019 तक अपडेट किए गए हैं।

रोजगार की तलाश करने वालों को रोजगार सृजन करने वाला बनाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए।

- वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर : डॉ. एम. वीरप्पा मोइली) ने 18 दिसंबर, 2017 को 'एनएसएसओ एवं सीएसओ की समीक्षा और देश में प्रोजेक्ट निगरानी/मूल्यांकन के लिए मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम सहित स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन मशीनरी की स्ट्रीमलाइनिंग' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी ने कहा कि नियमित रोजगार के अभाव और बेरोजगारी के डेटा के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यह गौर किया गया कि बेरोजगारी के सरकारी आंकड़े आउट-ऑफ-डेट और अवास्तविक हैं। कमिटी ने कहा कि रोजगार की स्थिति का आकलन करने और उपयुक्त नीतियों को बनाने के लिए रोजगार के सटीक और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए।<sup>73</sup>

**तालिका 6: रोजगार- बेरोजगारी पर वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर बेरोजगारी की दर (2015 में आखिरी बार किया गया)<sup>74</sup>**

	2011-12	2012-13	2013-14	2015-16
बेरोजगारी की दर	3.8%	4.7%	4.9%	5.0%

देश के नए इको-सिस्टम को व्यापक बनाने और उसे सहयोग देने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, मुद्रा, स्किल इंडिया जैसी पहल से रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत 18.2 लाख ग्रामीण उद्यमों का सृजन किया गया जिससे 3.78 लाख लोगों के लिए रोजगार मिला। स्किल्स इंडिया ने गति प्राप्त की और पिछले वर्ष के दौरान 76 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

- स्टार्ट-अप्स:** अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 के दौरान निगमित किए गए स्टार्ट-अप्स को वित्त एक्ट, 2016 के अनुसार तीन वर्षों के लिए इनकम टैक्स से छूट दी गई। केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान सरकार ने पात्र स्टार्ट-अप्स के लिए लाभ से जुड़ी कटौती की सीमा को बढ़ाकर सात वर्ष तक कर दिया।<sup>75</sup>
- नवंबर, 2018 तक 14,036 आवेदनों को स्टार्ट-अप्स के रूप में मान्यता दी गई। इनमें से 91 स्टार्ट-अप्स को कर छूट का लाभ देना मंजूर किया गया।<sup>76</sup>
- जुलाई 2016 में स्टार्ट-अप्स के लिए फंड्स का फंड बनाने को मंजूरी दी गई। चार वर्ष की अवधि के लिए फंड का कॉरपस 10,000 करोड़ रुपए है।<sup>77</sup> जून 2018 तक 550 स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेशन और आर्थिक सहायता के लिए मेंटर किया गया है।<sup>78</sup>

देश में कारोबार करना आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। आधुनिक तकनीक को आगे बढ़ाना मुख्य रणनीति है। इस मार्ग की संभावित बाधाओं की पहचान करने के लिए सरकार राज्यों के साथ कार्य कर रही है।

- **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस:** अक्टूबर 2018 में विश्व बैंक ने अपनी 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट जारी की। इसमें 2017 में भारत 190 देशों की सूची में 77 वीं रैंकिंग पर आ गया है। 2014 में भारत 189 में से 142वें स्थान पर था और इस साल उसकी रैंकिंग सुधर गई है।<sup>79,80</sup>
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने कई मानदंडों में परिवर्तन किए जिसके कारण उसकी कारोबारी रैंकिंग में सुधार हुआ। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सीमा पार व्यापार से जुड़ा समय और लागत में कमी, (ii) ऐसे परिवर्तन जिसके कारण कारोबार शुरू करने में कम समय लगता है, और (iii) कारोबार के विकास और वृद्धि के लिए ऋण हासिल करने में आसानी, इत्यादि।<sup>80</sup>

### शिक्षा

#### राष्ट्रपति के अभिभाषण 2014-2018:

सरकार देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थागत शिक्षण परिणाम में सुधार के लिए योजनाओं को लागू किया गया है।

- **सरकारी व्यय (केंद्र और राज्य):** जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर 2013-14 में कुल व्यय 3.1% जोकि 2017-18 में गिरकर 2.7% हो गया।<sup>81</sup>
- मुख्य शैक्षणिक संस्थानों में उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा फंडिंग एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना की गई थी।<sup>82</sup> 2022 तक उच्च शिक्षण संस्थानों की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एचईएफए को 1,00,000 करोड़ रुपए जुटाने का काम सौंपा गया है।<sup>83</sup>
- 27 जून, 2018 को भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट, 1956 का निरस्तीकरण) ड्राफ्ट बिल, 2018 को जारी किया गया।<sup>84</sup> यह बिल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रद्द करता है और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करता है। आयोग पाठ्यक्रमों में शिक्षण परिणामों और वाइस चांसलर्स के लिए पात्रता संबंधी मानदंडों को निर्दिष्ट करेगा और न्यूनतम मानदंडों का पालन न करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश देगा। इस प्रकार आयोग उच्च शिक्षा में शैक्षणिक मानदंडों को बरकरार रखेगा।
- नई शिक्षा नीति के विकास से संबंधित कमिटी (चेयर : टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम) ने 7 मई, 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।<sup>85</sup> रिपोर्ट कार्यान्वयन संबंधी कमियों को दूर

<p>विकास के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार 20 'इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस' बनाने पर काम कर रही है जिन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी।</p>	<p>करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हेतु नई शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कमिटी (चेयर : डॉ. के. कस्तूरीरंगन) बनाई गई।<sup>86</sup> कमिटी को 31 अगस्त, 2018 तक का समय दिया गया है।</li> <li>▪ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'समग्र शिक्षा' नामक योजना की शुरुआत की है जोकि स्कूल पूर्व से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक समग्र शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। इसमें तीन मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है: (i) सर्व शिक्षा अभियान, (ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और (iii) शिक्षक शिक्षा। 2018-19 के लिए इस योजना हेतु 34,000 करोड़ रुपए और 2019-20 के लिए 41,000 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है।<sup>87</sup></li> <li>▪ जुलाई 2018 में सरकार ने एक्सपर्ट कमिटी के सुझावों पर छह संस्थानों को 'इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस' घोषित किया।<sup>88</sup> इसमें तीन संस्थान निजी क्षेत्र के हैं: (i) जियो इंस्टीट्यूट, पुणे, (ii) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज़, पिलानी, और (iii) मनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। तीन सरकारी संस्थान निम्नलिखित हैं: (i) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूर, (ii) आईआईटी मुंबई, और (iii) आईआईटी दिल्ली।</li> </ul>
<b>हाउसिंग</b>	
<p>हाउसिंग एक मूलभूत अधिकार है। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के अंतर्गत सभी परिवारों के पास एक मकान होगा।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) : इस योजना के दो घटक हैं : ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण घटक, पीएमएवाई-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को नवंबर 2016 में शुरू किया गया था।</li> </ul>

निम्न आय वर्ग के परिवारों को आवासीय ऋण पर ब्याज सबसिडी देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। योजना का यह लक्ष्य है कि 2022 तक 4041 सांविधिक शहरों में दो करोड़ घर बनाए जाएंगे ताकि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों, शहरी गरीबों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को लोगों को लाभ मिले।

#### तालिका 7 : ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य और प्रगति<sup>89</sup>

	2016-17	2017-18	2018-19
लक्ष्य	42,79,190	32,04,663	25,11,972
उपलब्धि	32,21,901	21,11,404	14,21,850
हासिल %	75.2%	65.8%	56.6%

नोट: 2018-19 के डेटा 25 जनवरी, 2019 तक अपडेट किए गए हैं।

- पीएमएवाई- शहरी (पीएमएवाई-यू) को जून 2015 में शुरू किया गया।<sup>90</sup> शुरुआत में योजना में सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर तबके/निम्न आय वर्ग को शामिल किया गया था। फरवरी 2017 में योजना की ऋण से जुड़ी सबसिडी वाले घटक के लाभ को मध्यम आय वर्ग तक बढ़ाया गया।<sup>91</sup>

#### तालिका 8: पीएमएवाई-यू के अंतर्गत प्रगति<sup>92</sup>

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	3,222	4,598	16,531	9,013
मंजूर किए गए मकान	7,31,000	9,51,000	26,48,000	22,14,000
बनाए गए मकान	1,20,000	1,31,000	3,28,000	5,33,000

नोट: 2018-19 के डेटा 3 दिसंबर, 2018 तक अपडेट किए गए हैं।

- अपनी शुरुआत से पीएमएवाई-यू के लिए कुल 33,455 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मंजूर की गई और 68.5 लाख मकान बनाए गए। दिसंबर 2018 तक 12.45 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है।<sup>92,93</sup>

#### इंफ्रास्ट्रक्चर

शहर आर्थिक विकास के वाहक होते हैं। आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

- 2015-20 की अवधि के लिए स्मार्ट सिटीज़ और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का परिव्यय क्रमशः 48,000 करोड़ रुपए और 50,000 करोड़ रुपए है।<sup>94</sup>

- 19 जनवरी, 2018 तक 100 स्मार्ट सिटीज़ को चुना गया है। अपनी शुरुआत से अब तक स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने 100 शहरों में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के कुल 5,151 प्रॉजेक्ट्स को कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया है। 2018 तक इन शहरों में 2,05,018 करोड़ रुपए के कुल निवेश का प्रस्ताव है।<sup>95,96</sup>
- 30 नवंबर, 2018 तक 90,929 करोड़ रुपए मूल्य वाले 2,342 प्रॉजेक्ट्स का टेंडर दिया गया, जिनमें से 51,866 करोड़ रुपए मूल्य वाले 1,675 प्रॉजेक्ट्स शुरू किए गए। 10,079 करोड़ मूल्य वाले 525 प्रॉजेक्ट्स पूरे हो गए हैं।<sup>97</sup>

तालिका 9 : स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत जारी किए गए फंड्स<sup>98</sup>

	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
जारी किए गए फंड्स (करोड़ रुपए में)	1,469	4,493	3,978	9,939

- अमृत प्रॉजेक्ट आधारित दृष्टिकोण के जरिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं और गर्वनेंस संबंधी सुधारों के विकास पर केंद्रित है। राज्य की वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के आधार पर राज्यों को फंड्स जारी किए जाते हैं।
- 77,640 करोड़ रुपए मूल्य वाली कुल राज्य वार्षिक कार्रवाई योजनाओं (एसएएपी) में से 54,816 करोड़ रुपए मूल्य वाले 4,097 प्रॉजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। इनमें से 2,388 करोड़ रुपए मूल्य वाले 1,035 प्रॉजेक्ट्स पूरे हो गए हैं।<sup>95</sup>

ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास योजना को शुरू किया गया।

- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)** को 2015 में सभी गांवों को बिजलीकृत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो कि किसानों को पर्याप्त बिजली मिले और सभी उपभोक्ताओं को बिजली की नियमित आपूर्ति हो।<sup>99</sup>
- 28 अप्रैल, 2018 को बिजली से वंचित 100% गांवों को बिजलीकृत घोषित किया गया।<sup>100,101</sup> डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्यों को कुल 25,135 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई। अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन के लिए 11,996 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई।<sup>102</sup> निम्नलिखित तालिका में योजना की प्रगति प्रदर्शित की गई है।

तालिका 10: डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बिजलीकृत गांवों की संख्या<sup>103</sup>

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
बिजलीकृत गांवों की संख्या	7,108	6,015	3,736	1,515	18,374

नोट: 2018-19 के डेटा 28 मार्च, 2018 तक अपडेट किए गए हैं।

- दिसंबर 2014 में प्रारंभ एकीकृत बिजली विकास योजना का जनवरी 2019 तक परिव्यय 32,612 करोड़ रुपए है जिसमें 25,354 करोड़ रुपए का बजटीय सहयोग शामिल है।<sup>104</sup> इस योजना का उद्देश्य (i) शहरी क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना, (ii) शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर्स, फीडर्स और उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग करना, और (iii) वितरण के क्षेत्र में आईटी एनेबलमेंट को सुनिश्चित करना है।<sup>105</sup>
- दिसंबर 2018 तक योजना के लिए 7,116 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

सभी ग्रामीण बसाहटों को बारामासी सड़कों से जोड़ा गया है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 73,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)** का लक्ष्य मार्च 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों की सभी पात्र बिना जुड़ी बसाहटों को बारामासी सड़कों से जोड़ना है।<sup>106,107</sup>
- योजना की शुरुआत से 1.52 लाख बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य था। 29 जनवरी, 2019 तक 1.46 लाख (96%) बसाहटों को जोड़ा जा चुका है।<sup>108</sup> इसके अतिरिक्त राज्यों ने अपनी योजनाओं में 16,310 बसाहटों को कनेक्टिविटी प्रदान की है।<sup>109</sup> निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है कि योजना के अंतर्गत लक्ष्य क्या था, और कुल कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।

तालिका 11: पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रगति (किलोमीटर में)<sup>109</sup>

अवधि	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लक्ष्य	21,775	33,649	48,812	51,000	61,000
निर्मित सड़कें	38,056 (175%)	35,155 (104%)	47,446 (97%)	48,746 (96%)	16,856 (27%)

नोट: 2018-19 के डेटा नवंबर, 2018 तक अपडेट किए गए हैं। कुल किलोमीटर में नई कनेक्टिविटी सड़कें और पीएमजीएसवाई 1 और पीएमजीएसवाई 2 के अंतर्गत मौजूदा सड़कों का अपग्रेडेशन शामिल है।

रेलवे में बेहतर सेवा, यात्रियों की सुरक्षा और माल ढुलाई में बढ़ोतरी के लिए अनेक सुधार किए जा रहे हैं। 2019 तक दो समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर के कमीशन होने की उम्मीद है। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए सर्वाधिक 1.21 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है।

- **भारतीय रेलवे, 2015** के श्वेत पत्र के अनुसार हर वर्ष 4,500 किलोमीटर ट्रैक्स को नवीकृत किया जाना चाहिए।<sup>110</sup> 2014-15 और 2017-18 के बीच नवीनीकरण का औसत निर्धारित लक्ष्य श्वेत पत्र के सुझावों का 61% है। निम्नलिखित तालिका में लक्ष्य और 2014-15 एवं 2018-19 के बीच ट्रैक्स के वास्तविक नवीनीकरण को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 12: ट्रैक का नवीनीकरण: लक्ष्य बनाम उपलब्धि (किलोमीटर में)<sup>111,112</sup>

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
नवीनीकरण का लक्ष्य	2,200	2,500	2,668	3,600	5,000
वास्तविक नवीनीकरण	2,424 (110%)	2,794 (112%)	2,487 (93%)	4,405 (122%)	2,812 (56%)

नोट: 2018-19 के डेटा नवंबर, 2018 तक अपडेट किए गए हैं।

- 2018-19 के दौरान पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर पर काम जारी रहा। पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर में फुलेरा-अटारी क्षेत्र और पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर में खुर्जा-भदान क्षेत्र में मालगाड़ी के ट्रायल्स क्रमशः अगस्त और नवंबर, 2018 में किए गए। दोनों कॉरिडोर के कुछ हिस्से खोले गए हैं।<sup>112</sup>
- रेलवे मंत्रालय की सूचना के अनुसार समर्पित फ्रेट कॉरिडोर को 2020 तक पूरी तरह कमीशन कर दिया जाएगा।<sup>112</sup>
- यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इनमें 2018-19 से पूरी तरह एलएचबी डिजाइन वाले मेन लाइन कोच बनाने जैसे उपाय शामिल हैं। पिछले वर्षों के दौरान निर्माण इकाइयों में एलएचबी कोच का निर्माण बढ़ा है। 2004-05 से 2013-14 के दौरान 2,327 कोचेज़ बनाए गए जबकि 2014-15 से 2017-18 के दौरान 5,548 कोचेज़ बनाए गए। 2018-19 में 4,016 कोचेज़ की मैन्यूफैक्चरिंग का प्रस्ताव है।<sup>112</sup>
- रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 में नए सुरक्षा कोष, **राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष** की स्थापना की गई। इस सुरक्षा कोष का इस्तेमाल मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने और सिग्नलिंग प्रणालियों में सुधार और उसके आधुनिकीकरण

के लिए किया जा रहा है। 2017 के लिए रेल संरक्षा कोष हेतु 20,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। इनमें से 15,000 करोड़ रुपए सकल बजटीय सहयोग द्वारा और बाकी के 5,000 करोड़ रुपए रेलवे द्वारा दिए गए थे।

- इसके अतिरिक्त सरकार ने ब्रॉड गेज पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को हटाने या उसे मानवयुक्त करने की योजना बनाई है। 1 अप्रैल, 2018 तक 5,792 मानवरहित लेवल क्रॉसिंग थे, जिनमें से 3,479 ब्रॉड गेज पर, 1,135 मीटर गेज पर और 1178 नैरो गेज पर थे।<sup>113</sup>
- 2018 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने वाली नई ट्रेनें और कोच शुरू कीं। इसलिए अब तक हमसफर ट्रेन, अंत्योदय ट्रेन, दीनदयालु कोच, तेज ट्रेन, विस्टाडोम कोच और आधुनिक रेक्स जिनमें जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणालियों सीसीटीवी और फायर एंड स्मोक डिटेक्शन प्रणालियों जैसी सुविधाएं शामिल हैं, को शुरू किया गया है।<sup>112</sup>
- नकद रहित और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे मंत्रालय ने अनेक प्रकार की पहल की है। इनमें विभिन्न यात्री रिजर्वेशन प्रणालियों में प्वाइंट ऑफ सेल मशीन्स लगाना, टिकटों की ऑनलाइन खरीद पर बुकिंग चार्ज को वापस लेना शामिल है। साथ ही मंत्रालय ने रिजर्व/अनरिजर्व टिकटों की बुकिंग के भुगतान के लिए युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और भारत इंटरफेस ऑफ मनी (भीम) को स्वीकार करना शुरू कर दिया है।<sup>112</sup>

### स्वास्थ्य और स्वच्छता

#### राष्ट्रपति के अभिभाषण 2014-2018:

स्वच्छता के अभाव में गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। 1.4 लाख गांवों, 450 लाख से अधिक शहरों, 77 जिलों और 3 राज्यों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है।

- **स्वच्छ भारत मिशन:** स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्ति और म्यूनिसिपल ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रबंधन को हासिल करना था।<sup>114,115</sup>
- **एसबीएम शहरी** को हासिल करने के लिए 29 जनवरी, 2019 तक 24,130 घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।<sup>116</sup> 29 जनवरी, 2019 तक

व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए 1,04,02,997 आवेदन प्राप्त हो चुके थे जिनमें से 57,38,788 (55%) का निर्माण किया जा चुका है।<sup>116</sup>

- एसबीएम ग्रामीण के अंतर्गत 30 जनवरी, 2019 तक 9,19,97,843 घरों में व्यक्तिगत शौचालय बनाए जा चुके हैं (लक्ष्य का 98.81%, जबकि 2 अक्टूबर, 2014 को 38.70% शौचालयों का निर्माण किया गया था)।<sup>117</sup>

**तालिका 13: एसबीएम-ग्रामीण के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों की संख्या<sup>118</sup> (लाख में)**

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बनाए गए शौचालय	49	126	218	297	216

नोट: 2018-19 के डेटा 30 जनवरी, 2018 तक अपडेट किए गए हैं।

- 2015-16 में 47,026 की तुलना में 5,48,452 गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया (लक्ष्य का 91.33%)<sup>119</sup>

**तालिका 14: ओडीएफ गांवों की संख्या (कुल मिलाकर)<sup>119</sup>**

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ओडीएफ घोषित किए गए गांव	47,026	1,82,653	3,49,654	5,15,455
ओडीएफ सत्यापित किए गए गांव	46,811 (99%)	1,80,125 (98%)	3,36,693 (96%)	4,58,869 (89%)

नोट: 2018-19 के डेटा 30 जनवरी, 2019 तक अपडेट किए गए हैं।

- एसबीएम ग्रामीण को विश्व बैंक के सपोर्ट प्रॉजेक्ट के अंतर्गत स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) द्वारा राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) 2017-18 में पाया गया कि ग्रामीण भारत के 93.4% घर उन्हें उपलब्ध शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। एनएआरएसएस ने 95.6% गांवों के ओडीएफ दर्ज की पुष्टि की जिन्हें पहले ओडीएफ घोषित किया गया था, और विभिन्न जिलों/राज्यों द्वारा ओडीएफ सत्यापित किया गया था। सर्वेक्षण 2017 में नवंबर मध्य से 2018 में मार्च मध्य के बीच किया

	<p>गया जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6,136 ग्रामीण घर शामिल थे।<sup>120</sup></p>
<p>सरकार देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर तबकों को सस्ती और सुगम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत उपचार के परंपरागत तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।</p> <p>सरकार ने 'प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बच्चे' के टीकाकरण के लिए 'इंटीग्रेटेड मिशन इंद्रधनुष' की शुरुआत की।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मिशन</b> : जुलाई, 2014 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मिशन के लिए व्यापक बैकग्राउंड पेपर तैयार करने के लिए एक दल बनाया गया।<sup>121</sup> इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।</li> <li>▪ <b>आयुष्मान भारत</b>: 2018-19 के आम बजट में सरकार ने आयुष्मान भारत के अंग के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र में दो मुख्य कार्यक्रमों की घोषणा की।<sup>122</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <b>स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र</b>: आयुष्मान भारत का लक्ष्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले 1,50,000 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र बनाना है। इन केंद्रों में मातृत्व, बाल स्वास्थ्य सेवाएं और गैर संचारी रोगों को शामिल किया गया है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।<sup>123</sup></li> <li>(ii) <b>प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)</b>: इस योजना की शुरुआत सितंबर, 2018 में की गई थी और दस करोड़ गरीब और कमजोर परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इसके दायरे में आएंगे।<sup>124</sup> यह द्वितीयक और तृतीय देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार को पांच लाख रुपए प्रदान करेगी। इस योजना के लिए 2018-19 हेतु 3,125 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।<sup>125</sup> योजना राज्यों के सहयोग से लागू की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 30 राज्यों ने इसकी शुरुआत कर दी है।<sup>126</sup> 10 दिसंबर, 2018 तक इस योजना के अंतर्गत 7,63,17,810 लाभार्थियों का नामांकन हो चुका है और राज्यों को 818 करोड़ रुपए आबंटित किए जा चुके हैं।<sup>126</sup></li> </ul> </li> <li>▪ <b>मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य</b> शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों के टीकाकरण से वंचित और आंशिक टीकाकरण वाले बच्चों को कवर करना है। 2017-18 में इस योजना के अंतर्गत 319 लाख बच्चों और 81 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।<sup>127</sup></li> </ul>

मूल्य संवर्धित आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) सेवा को बढ़ावा देने, आयुष दवाओं की उपलब्धता में सुधार करने और आयुष शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई।

- दिसंबर 2017 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3,013 जन औषधि केंद्र सस्ती दरों पर दवाएं प्रदान कर रहे हैं।<sup>128</sup> इस योजना का लक्ष्य मार्च 2017 तक 3,000 केंद्र स्थापित करना था।
- 2018-19 और 2019-20 के लिए प्रति वर्ष 1,000 अतिरिक्त केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।<sup>129</sup>
- **आयुष:** 15 दिसंबर, 2017 को सरकार ने 2017-18 से 2019-20 के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) को जारी रखने को मंजूरी दी। तीन वर्ष की अवधि के लिए इसका परिव्यय 2400 करोड़ रुपए है।

**अस्वीकरण:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

<sup>1</sup> “Press Note on First Advance Estimates of National Income: 2018-19”, Ministry of Statistics and Program Implementation, Press Information Bureau, [http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/Press%20note%20for%20first%20advance%20estimates%202018-19.pdf](http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/Press%20note%20for%20first%20advance%20estimates%202018-19.pdf).

<sup>2</sup> “Second Advance Estimates of National Income, 2017-18”, Ministry of Statistics and Program Implementation, Press Information Bureau, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176847>

<sup>3</sup> “Second Advance Estimates of National Income, 2016-17”, Ministry of Statistics and Program Implementation, Press Information Bureau, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=158734>

<sup>4</sup> “Press Note on Advance Estimates of National Income 2015-16”, Ministry of Statistics and Programme Implementation, February 8, 2016, [http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/nad\\_PR\\_8feb16.pdf](http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/nad_PR_8feb16.pdf).

<sup>5</sup> “Press Note on Advance Estimates of National Income 2014-15”, Ministry of Statistics and Programme Implementation, February 8, 2015, [http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/nad\\_press\\_release\\_9feb15.pdf](http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/nad_press_release_9feb15.pdf).

<sup>6</sup> Overview-Monetary Policy, Reserve Bank of India, [https://www.rbi.org.in/scripts/FS\\_Overview.aspx?fn=2752](https://www.rbi.org.in/scripts/FS_Overview.aspx?fn=2752).

<sup>7</sup> S.O. 2623 (E), e-Gazette of India, Ministry of Finance, August 5, 2016, <http://egazette.nic.in/WriteReadData/2016/171115.pdf>.

<sup>8</sup> “Press Release Consumer Price Index Numbers on Base 2012=100 for Rural, Urban and Combined for the Month of December 2018”, Ministry of Statistics and Programme Implementation, January 14, 2019, [http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/Press%20Statement\\_0.pdf](http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/Press%20Statement_0.pdf).

<sup>9</sup> “Press Release Consumer Price Index Numbers on Base 2012=100 for Rural, Urban and Combined for the Month of December 2017”, Ministry of Statistics and Programme Implementation, January 12, 2018, [http://mospi.nic.in/sites/default/files/press\\_release/CPI\\_PR12jan17th.pdf](http://mospi.nic.in/sites/default/files/press_release/CPI_PR12jan17th.pdf).

<sup>10</sup> “Total expenditure for the fiscal year 2018-19 is estimated to be over Rs 24.42 lakh crore; Fiscal deficit to be 3.3% of the GDP for the coming fiscal year”, Press Information Bureau, February 1, 2018, <http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1518538>

<sup>11</sup> Monthly Accounts, Union Government Accounts at A Glance, Controller General of Accounts, Ministry of Finance, <http://www.cga.nic.in/Accountproc.aspx>

<sup>12</sup> FDI Statistics, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Manufacturing, last accessed on October 23, 2018, [http://dipp.nic.in/sites/default/files/FDI\\_FactSheet\\_29June2018.pdf](http://dipp.nic.in/sites/default/files/FDI_FactSheet_29June2018.pdf)

<sup>13</sup> “FDI policy further liberalized in key sectors, Cabinet approves amendments in FDI policy”, Cabinet, Press Information Bureau, January 10, 2018, <http://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1516118>.

<sup>14</sup> “Foreign Exchange Reserves,” Reserve Bank of India, January 25, 2019, <https://www.rbi.org.in/Scripts/WSSView.aspx?Id=22729>.

- <sup>15</sup> RBI Database, <https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=home>.
- <sup>16</sup> “Developments in India’s Balance of Payments during the first quarter of 2018-19”, Reserve Bank of India, Press Release, September 7, 2018, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR576897D0BAF61DD4A788CFE79EDD3D3CB37.PDF>
- <sup>17</sup> “Press Note on Estimates of Gross Domestic Product for the second quarter (July-September) of 2018-19”, Ministry of Statistics and Programme Implementation, November 30, 2018, [http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/PRESS\\_NOTE-Q2\\_2018-19%2030.11.2018.pdf](http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PRESS_NOTE-Q2_2018-19%2030.11.2018.pdf)
- <sup>18</sup> “GST roll-out – Complete transformation of the Indirect Taxation Landscape; Some minute details of how it happened, Ministry of Finance”, Press Information Bureau, June 30, 2017, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=167023>.
- <sup>19</sup> “Recapitalisation of Public Sector Banks”, Ministry of Finance, Press Information Bureau, January 5, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=175368>.
- <sup>20</sup> “Recapitalisation of Public Sector Banks”, Ministry of Finance, Press Information Bureau, December 14, 2018, <http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1556008>.
- <sup>21</sup> Statistical Tables Relating to Banks in India, Database on Indian Economy, Reserve Bank of India, <https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#14>
- <sup>22</sup> Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, <http://www.prsindia.org/billtrack/the-insolvency-and-bankruptcy-bill-2015-4100/>
- <sup>23</sup> Quarterly Newsletter for April to June 2018, Insolvency and Bankruptcy Board of India, [https://ibbi.gov.in/Newsletter\\_IBBI\\_April\\_jun2018.pdf](https://ibbi.gov.in/Newsletter_IBBI_April_jun2018.pdf)
- <sup>24</sup> Table No. 160, Handbook of Statistics on the Indian Economy, Reserve Bank of India, <https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook%20of%20Statistics%20on%20Indian%20Economy>
- <sup>25</sup> Annual Report 2017-18, Reserve Bank of India, August 29, 2018, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/0ANREPO>
- <sup>26</sup> “Year End Review-Key Achievements:2018”, Ministry of Electronics and IT, Press Information Bureau, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186697>.
- <sup>27</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 1319, Ministry of Finance, December 22, 2017, <http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=59329&lsno=16>.
- <sup>28</sup> “Only Rs. 5,000 cr deposited under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: Hasmukh Adhia”, The Hindu Business Line, June 1, 2017, <http://www.thehindubusinessline.com/economy/only-rs-5000-cr-deposited-under-pradhan-mantri-garib-kalyan-yojana-hasmukh-adhia/article9717564.ece>
- <sup>29</sup> “Official data for PMGKY: Unaccounted funds at just Rs 5000 crore”, The Indian Express, June 2, 2017, <http://indianexpress.com/article/business/official-data-for-pmgky-unaccounted-funds-at-just-rs-5000-crore-4685089/>.
- <sup>30</sup> “The Undisclosed Foreign Income and Assets Bill, 2015,” PRS Legislative Research, April 20, 2015, [http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill\\_files/Bill\\_Summary\\_-\\_Undisclosed\\_Foreign\\_Income\\_0.pdf](http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Bill_Summary_-_Undisclosed_Foreign_Income_0.pdf).
- <sup>31</sup> “The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018”, PRS Legislative Research, March 16, 2018, [http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill\\_files/Fugitive%20Economic%20Offenders%20Bill%20-%20Bill%20Summary.pdf](http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Fugitive%20Economic%20Offenders%20Bill%20-%20Bill%20Summary.pdf).
- <sup>32</sup> “The Prevention of Corruption (Amendment) Bill”, PRS Legislative Research, February 12, 2014, [http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill\\_files/Bill\\_Summary-Prevention\\_of\\_Corruption\\_1.pdf](http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Bill_Summary-Prevention_of_Corruption_1.pdf).
- <sup>33</sup> Direct Benefit Transfer, Government of India, last accessed on January 27, 2019, <https://dbt.bharat.gov.in/>.
- <sup>34</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 174, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 11, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU174.pdf>.
- <sup>35</sup> Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Progress Report, last accessed on January 31, 2019, <https://pmjdy.gov.in/account>
- <sup>36</sup> Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Archives, last accessed on October 23, 2018, <https://pmjdy.gov.in/archive>
- <sup>37</sup> Unique Identification Authority of India, State/UT wise Aadhaar saturation, last accessed on January 27, 2018, <https://uidai.gov.in/images/state-wise-aadhaar-saturation.pdf>.
- <sup>38</sup> “Key Achievements:2017”, Ministry of Electronics and IT, December 29, 2017, <http://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1514598>.
- <sup>39</sup> “730 million Internet users are anticipated in the country by 2020-NASSCOM.” Ministry of Communications, March 27, 2017, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=159967>.
- <sup>40</sup> PAHAL-Direct Benefits Transfer for LPG(DBTL) Consumers Scheme Ministry of Petroleum and Natural Gas, last accessed on October 23, 2018, <http://petroleum.nic.in/dbt/whatisdbtl.html>.
- <sup>41</sup> Rajya Sabha Unstarred Question No. 1889, Ministry of Petroleum and Natural Gas, January 3, 2018, <http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx>.
- <sup>42</sup> Rajya Sabha Unstarred Question No. 1893, Ministry of Petroleum and Natural Gas, January 3, 2018, <http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx>.
- <sup>43</sup> “DBTL under implementation in 715 districts”, Ministry of Petroleum and Natural Gas, December 31, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186937>.
- <sup>44</sup> Rajya Sabha Starred Question No. 36, Ministry of Petroleum and Natural Gas, July 19, 2017, <http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx>.
- <sup>45</sup> “Year End Review-2018-Ministry of Finance”, Ministry of Finance, January 2, 2019, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=187008>.
- <sup>46</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 2536, Ministry of Communications, January 3, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU2536.pdf>.
- <sup>47</sup> “PM launches India Post Payments Bank – a major initiative towards financial inclusion”, Press Information Bureau, September 1, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=183218>
- <sup>48</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 17, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 11, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AS17.pdf>.

- <sup>49</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 4077, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, March 20, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/14/AU4077.pdf>.
- <sup>50</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 2102, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, July 31, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/15/AU2102.pdf>.
- <sup>51</sup> Lok Sabha Starred Question No. 282, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 7, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/15/AS282.pdf>.
- <sup>52</sup> "Price Stabilization Fund", Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Press Information Bureau, March 28, 2017, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=160050>
- <sup>53</sup> Rajya Sabha Unstarred Question No. 4501, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, April 6, 2018, <http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx>.
- <sup>54</sup> Food Corporation of India, Minimum Support Price of Wheat and Paddy, <http://fci.gov.in/procurements.php?view=89>
- <sup>55</sup> "Minimum Support Prices Recommended by CACP and Fixed by Government", Commission for Agricultural Costs and Prices, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, <https://cacp.dacnet.nic.in/ViewQuestionare.aspx?Input=2&DocId=1&PageId=42&KeyId=635>.
- <sup>56</sup> "Cabinet approves doubling of Government guarantee from Rs 9,500 crore to Rs 19,000 crore for procurements of pulses and oilseeds at MSP under Price Support Scheme by NAFED", Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Press Information Bureau, February 28, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176893>
- <sup>57</sup> "Release of funds under PMKSY", Ministry of Water Resources, Press Information Bureau, December 27, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186853>.
- <sup>58</sup> Unstarred question No. 2295, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, July 31, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/15/AU2295.pdf>.
- <sup>59</sup> "Special Service and Features", Press Information Bureau, December 23, 2015, <http://pib.nic.in/newsite/mbErel.aspx?relid=133855>.
- <sup>60</sup> "Soil Health Cards", Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Press Information Bureau, December 18, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186563>.
- <sup>61</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 2295, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, July 31, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/15/AU2295.pdf>.
- <sup>62</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 1297, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 18, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU1297.pdf>.
- <sup>63</sup> "Year End Review, Ministry of Labour and Employment", December 18, 2017, <http://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1512998>.
- <sup>64</sup> Rate of Minimum Wages, Ministry of Labour and Employment, March 1 2017, [https://labour.gov.in/sites/default/files/MX-M452N\\_20170518\\_132440.pdf](https://labour.gov.in/sites/default/files/MX-M452N_20170518_132440.pdf).
- <sup>65</sup> Gazette Number 173, Ministry of Labour and Employment, January 19, 2017, Gazette of India, <http://egazette.nic.in/WriteReadData/2017/173724.pdf>.
- <sup>66</sup> "Bill Summary: Code of Wages: 2017", PRS Legislative Research, August 22, 2017, [http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill\\_files/The%20Code%20on%20Wages%20Bill%20Summary.pdf](http://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/The%20Code%20on%20Wages%20Bill%20Summary.pdf).
- <sup>67</sup> "Year End Review-2018", Ministry of Labour and Employment, December 13, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186346>.
- <sup>68</sup> Year-wise progress of TUFs, Office of Textile Commissioner, [http://www.txcindia.gov.in/html/mdo2007\\_4.pdf](http://www.txcindia.gov.in/html/mdo2007_4.pdf)
- <sup>69</sup> "Year End Review 2016: Ministry of Textiles", Press Information Bureau, December 28, 2016, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155912>
- <sup>70</sup> "Year End Review-2018", Ministry of Textiles, Press Information Bureau, December 20, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186673>.
- <sup>71</sup> "Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana", Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, December 17, 2018, <http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1556205>.
- <sup>72</sup> Pradhan Mantri MUDRA Yojana, last accessed on October 23, 2018, <https://www.mudra.org.in/>
- <sup>73</sup> PRS Report Summary, Review of National Statistical Survey Office (NSSO) and Central Statistics Office (CSO) [http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1514530383\\_SCR%20Summary-%20Review%20of%20\(NSSO\)%20and%20\(CSO\).pdf](http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1514530383_SCR%20Summary-%20Review%20of%20(NSSO)%20and%20(CSO).pdf)
- <sup>74</sup> Annual Report 2017-18, Ministry of Labour and Employment, [https://labour.gov.in/sites/default/files/ANNUAL\\_REPORT\\_2017-18-ENGLISH.pdf](https://labour.gov.in/sites/default/files/ANNUAL_REPORT_2017-18-ENGLISH.pdf)
- <sup>75</sup> Start-Up India, The Status Report; Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, January 4, 2018, <http://www.startupindia.gov.in/status.php>
- <sup>76</sup> "Start Up India: Status Report 2018", Ministry of Commerce and Industry, November 23, 2018, [https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/Status\\_report\\_on\\_Startup\\_India.pdf](https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/Status_report_on_Startup_India.pdf)
- <sup>77</sup> "Major initiatives and accomplishments of Department of Industrial Policy and Promotion-2016", Ministry of Commerce and Industry, Press Information Bureau, January 4, 2016, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=156108>
- <sup>78</sup> "Over 550 startups mentored for incubation and funding support", Ministry of Commerce and Industry, July 23, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=180839>.
- <sup>79</sup> "Doing Business 2019", World Bank, [http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report\\_print-version.pdf](http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_print-version.pdf)
- <sup>80</sup> "Doing Business 2018", World Bank, <http://www.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>
- <sup>81</sup> Economic Survey 2017-18, Chapter 10, [http://mofapp.nic.in/8080/economicsurvey/pdf/167-185\\_Chapter\\_10\\_Economic\\_Survey\\_2017-18.pdf](http://mofapp.nic.in/8080/economicsurvey/pdf/167-185_Chapter_10_Economic_Survey_2017-18.pdf)
- <sup>82</sup> Cabinet approves establishment of Higher Education Financing Agency for creating capital assets in higher educational institutions, Press Information Bureau, Cabinet, September 12, 2016
- <sup>83</sup> "Boost to Higher Education", Press Information Bureau, Cabinet, July 4, 2018.

- <sup>84</sup> “Government approves draft Act for setting up of Higher Education Commission of India by repealing UGC Act”, Ministry of Human Resource Development, Press Information Bureau, June 27, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=180247>
- <sup>85</sup> National Policy on Education, 2016, Ministry of Human Resource Development, Report of the Committee for Evolution of the New Education Policy, <http://nuepa.org/New/download/NEP2016/ReportNEP.pdf>
- <sup>86</sup> “Government constitutes a committee to prepare the final draft of National Education Policy”, Ministry of Human Resource Development, Press Information Bureau, June 26, 2017, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=166900>.
- <sup>87</sup> “Ministry of HRD launches ‘Samagra Siksha’ scheme for holistic development of school education”, Press Information Bureau, Ministry of Human Resource Development, May 24, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=179528>.
- <sup>88</sup> “Government declares 6 educational ‘Institutions of Eminence’ ; 3 Institutions from Public Sector and 3 from Private Sector shortlisted”, Ministry of Human Resource Development, July 11, 2018, [http://mhrd.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/IOE\\_PR.pdf](http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/IOE_PR.pdf)
- <sup>89</sup> High Level Physical Progress Report, PMAYG, Ministry of Rural Development, last accessed on January 25, 2019, <https://rhreporting.nic.in/netiay/PhysicalProgressReport/physicalprogressreport.aspx>
- <sup>90</sup> “Housing for All by 2022” Mission - National Mission for Urban Housing”, Press Information Bureau, June 15, 2015, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=122576>
- <sup>91</sup> “Cabinet approves Extension of tenure of loans under the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) from 15 to 20 years”, Press Information Bureau, February 1, 2017, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=157827>
- <sup>92</sup> “Year Ender-6-PMAY-Ministry of Housing and Urban Affairs, 2018”, Press Information Bureau, December 27, 2018, <http://pib.nic.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1557462>.
- <sup>93</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 1196, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 18, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU1196.pdf>.
- <sup>94</sup> “Union Cabinet approves Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation and Smart Cities Mission to drive economic growth and foster inclusive urban development”, Press Information Bureau, April 29, 2015, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=119925>.
- <sup>95</sup> “Shillong (Meghalaya) gets selected as the 100th Smart City”, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Press Information Bureau, June 20, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=180063>
- <sup>96</sup> “Year Ender- Ministry of Housing and Urban Affairs-2018”, Ministry of Housing and Urban Affairs, Press Information Bureau, December 31, 2018, <http://pib.nic.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1557895>.
- <sup>97</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 37, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 11, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU37.pdf>.
- <sup>98</sup> <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AS211.pdf>
- <sup>99</sup> “Prime Minister to Launch Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana in Patna”, Ministry of Power, Press Information Bureau, July 23, 2015, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=123595>.
- <sup>100</sup> “Year End Review 2018-Ministry of Power”, Ministry of Power, Press Information Bureau, December 12, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186285>.
- <sup>101</sup> Lok Sabha Starred Question No. 89, Ministry of Power, December 21, 2017, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AS89.pdf>.
- <sup>102</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 3893, Ministry of Power, January 3, 2019, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU3893.pdf>.
- <sup>103</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 2573, Ministry of Power, August 2, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/15/AU2573.pdf>.
- <sup>104</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 3689, Ministry of Power, January 3, 2019, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU3689.pdf>.
- <sup>105</sup> “Integrated Power Development Scheme (IPDS)”, Ministry of Power, [http://www.ipds.gov.in/Form\\_IPDS/About\\_IPDS.aspx](http://www.ipds.gov.in/Form_IPDS/About_IPDS.aspx).
- <sup>106</sup> PMGSY Guidelines, Ministry of Rural Development, last accessed on October 23, 2018. <http://pmsgsy.nic.in/>.
- <sup>107</sup> “Implementation of PMGSY”, Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, December 27, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186837>.
- <sup>108</sup> Online Management, Monitoring and Accounting System (OMMAS), Pradhan Mantri, Gram Sadak Yojana, last accessed on October 23, 2018, <http://omms.nic.in/Home/CitizenPage/#>.
- <sup>109</sup> “PMGSY”, Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, December 13, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186369>.
- <sup>110</sup> Indian Railways, Lifeline of a Nation, White Paper, Ministry of Railways, February 2015, [http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/finance\\_budget/Budget\\_2015-16/White\\_Paper-English.pdf](http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/finance_budget/Budget_2015-16/White_Paper-English.pdf).
- <sup>111</sup> “Status of Track Renewal in Railways”, Ministry of Railways, Press Information Bureau, December 29, 2017, <http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1514627>.
- <sup>112</sup> “Initiatives & Achievements of Ministry of Railways in the year 2018”, Ministry of Railways, Press Information Bureau, December 29, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186913>.
- <sup>113</sup> “Elimination of Unmanned Level Crossings in Railways”, Ministry of Railways, Press Information Bureau, December 12, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186322>.
- <sup>114</sup> “Swachh Bharat Mission needs to become a Jan Andolan with participation from every stakeholder: Hardeep Puri, 1,789 Cities have been declared ODF conference on PPP model for waste to energy projects”, Ministry of Housing and Urban Affairs, Press Information Bureau, November 30, 2017, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=173995>.
- <sup>115</sup> “PM launches Swachh Bharat Abhiyaan”, Prime Minister’s Office, Press Information Bureau, October 2, 2014, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=110247>.

- <sup>116</sup> “Individual Household Latrine Application”, Ministry of Housing and Urban Affairs, last accessed on January 30, 2019, <http://swachhbharaturban.gov.in/ihhl/RPTApplicationSummary.aspx>.
- <sup>117</sup> Swachh Bharat Mission (Gramin), Ministry of Drinking Water and Sanitation, last accessed on January 30, 2019, <https://sbm.gov.in/sbmdashboard/Default.aspx>.
- <sup>118</sup> Swachh Bharat Mission (Gramin), Ministry of Drinking Water and Sanitation, last accessed on January 30, 2019, <http://sbm.gov.in/sbmdashboard/IHHL.aspx>.
- <sup>119</sup> Swachh Bharat Mission (Gramin), Ministry of Drinking Water and Sanitation, last accessed on January 30, 2019, <http://sbm.gov.in/sbmdashboard/ODF.aspx>.
- <sup>120</sup> “Independent Verification of Swachh Bharat Gramin confirms 93% usage of toilets”, Ministry of Drinking Water and Sanitation, Press Information Bureau, March 27, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178030>
- <sup>121</sup> “Rolling out of National Health Assurance Mission”, Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, July 15, 2014, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=106608>
- <sup>122</sup> “Ayushman Bharat for a new India -2022, announced”, Ministry of Finance, Press Information Bureau, February 1, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176049>
- <sup>123</sup> About NHA, Ayushman Bharat, Ministry of Health and Family Welfare, <https://www.pmjay.gov.in/about-nha>.
- <sup>124</sup> “Ayushman Bharat –Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (AB-PMJAY) to be launched by Prime Minister Shri Narendra Modi in Ranchi, Jharkhand on September 23, 2018”, Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, September 22, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=183624>.
- <sup>125</sup> National Health Accounts, estimates for 2014-15 Ministry of Health and Family Welfare, <https://mohfw.gov.in/newshighlights/national-health-accounts-estimates-india-2014-15>.
- <sup>126</sup> Lok Sabha Unstarred Question No. 880, Ministry of Health and Family Welfare, December 14, 2018, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/16/AU880.pdf>
- <sup>127</sup> “Mission Indradhanush”, Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, August 10, 2018, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=181816>.
- <sup>128</sup> “3,013 Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) Kendras functional in 33 States/UTs, Ministry of Chemicals and Fertilizers”, December 19, 2017, <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174500>.
- <sup>129</sup> Lok Sabha Unstarred Question No 669, Ministry of Chemicals and Fertilizers, December 19, 2017, <http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU669.pdf>.